II. राजकोषीय स्थिति

संयुक्त सरकारी वित्त : वर्ष 2007-08

वर्ष 2007-08 के दौरान प्रमुख राजकोषीय संकेतक, यथा, सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), राजस्व घाटा और केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त का प्राथमिक घाटा 2006-07 के लिए बजट में संशोधित अनुमान से जीडीपी के 0.7-0.9 प्रतिशत अंक तक कम होने की बात कही गयी है (सारणी 15) । बजट में राज्यों के राजस्व अधिशेष प्रमुख घाटा संकेतकों में अभिकल्पित कमी के लिए महत्वपूर्ण अंशदायी घटक होंगे । वर्ष 2007-08 के दौरान केंद्र और राज्य सरकार, दोनों, के वित्त का एक महत्वपूर्ण लक्षण विकास संबंधी व्यय के लिए अधिक आबंटन होगा,

सारणी 15: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी का प्रतिशत)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	कुल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं*
1	2	3	4	5
केंद्र				
2002-03	1.1	4.4	5.9	63.4
2003-04	-0.03	3.6	4.5	62.8
2004-05	-0.04	2.5	4.0	63.8
2005-06	0.4	2.6	4.1	63.4
2006-07 संअ	0.1	2.0	3.7	61.5
	(-0.2)	(1.9)	(3.5)	
2007-08 बअ	-0.2	1.5	3.3	59.2
राज्य				
2002-03	1.3	2.2	4.2	32.5
2003-04	1.5	2.2	4.5	33.4
2004-05	0.7	1.2	3.5	33.3
2005-06	0.1	0.04	2.4	32.5
2006-07 संअ	0.4	-0.01	2.6	30.3
2007-08 बअ	-0.02	-0.4	2.1	29.2
संयुक्त				
2002-03	3.1	6.6	9.6	80.7
2003-04	2.1	5.8	8.5	81.4
2004-05	1.4	3.7	7.5	82.4
2005-06	1.0	2.6	6.6	80.5
2006-07 संअ	0.7	2.0	6.2	77.0
2007-08 बअ	0.0	1.2	5.3	74.2

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान

* : बाह्य देयताएं ऐतिहासिक विनिमय दरों पर शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े अनंतिम खातों से संबंधित हैं।

2. ऋणात्मक संकेत अधिशेष दर्शाते हैं।

3. राज्यों के संबंध में आंकड़े 2005-06 से आगे अनंतिम हैं और 27 राज्यों (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित) से संबंधित हैं, जिनमें से दो लेखानुदान हैं।

सारणी 16: केन्द्र और राज्यों के संयुक्त सकल राजस्व घाटे का वित्तीय पैटर्न

(करोड़ रुपये)

वर्ष	बाज़ार उधार	राज्य भविष्य निधियाँ	लघु बचत	बाह्य सहायता	अन्य	सकल राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5	6	7
2003-04	1,36,156	12,014	67,642	-13,488	32,177	2,34,501
	(58.1)	(5.1)	(28.8)	(-5.8)	(13.7)	
2004-05	85,498	13,139	87,690	14,753	33,641	2,34,721
	(36.4)	(5.6)	(37.4)	(6.3)	(14.3)	
2005-06	1,20,164	14,687	89,836	7,472	2,630	2,34,789
	(51.2)	(6.3)	(38.3)	(3.2)	(1.1)	
2006-07 सं.अ.	1,28,245	14,437	61,600	7,892	44,887	2,57,061
	(49.9)	(5.6)	(24.0)	(3.1)	(17.5)	
2007-08 ब.अ.	1,34,544	15,583	57,500	9,111	30,459	2,47,197
	(54.4)	(6.3)	(23.3)	(3.7)	(12.3)	

ब.अ. : बजट अनुमान सं.अ. : संशोधित अनुमान

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत हैं ।

जबकि राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया जारी रहेगी । राजकोषीय समेकन प्रक्रिया और आर्थिक विकास में उछाल को देखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त ऋण-जीडीपी अनुपात मार्च 2007 के अंत में 77.0 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2008 के अंत में 74.2 प्रतिशत रहने की बात बजट में कही गयी है (सारणी 15) ।

वर्ष 2007-08 के दौरान बाजार उधारों से 54.4 प्रतिशत संयुक्त जीएफडी का वित्तपोषण किया जायेगा, जिसके बाद लघु बचतों (23.3 प्रतिशत) का स्थान आता है (सारणी 16)।

केंद्र की राजकोषीय स्थिति : वर्ष 2007-08

वर्ष 2007-08 के दौरान बजट में केंद्र का राजस्व घाटा और जीएफडी, जो जीडीपी के क्रमशः 1.5 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत तक रहेगा, वह वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित अनुमानों से 0.5 प्रतिशत अंक और 0.4 प्रतिशत अंक कम होगा । अप्रैल-मई 2007 के लिए केंद्र सरकार के वित्त से संबंधित उपलब्ध जानकारी से यह संकेत मिलता है कि सभी प्रमुख घाटा संकेतक सुनिश्चित शब्दों में एक वर्ष पूर्व की तुलना में नीचे थे (चार्ट 5) । जीएफडी भी

चार्ट 5: केन्द्र के प्रमुख घाटा संकेतक

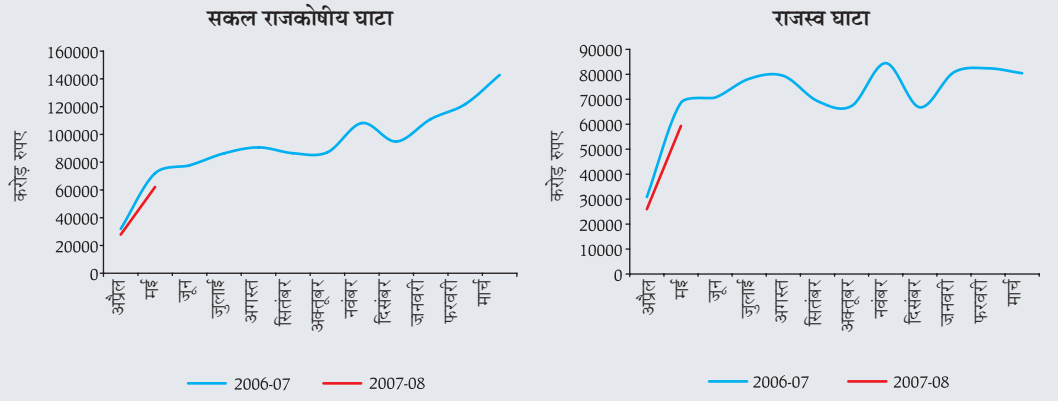

बजट अनुमानों के प्रतिशत के संदर्भ में अप्रैल-मई 2006 की तुलना में कम था ।

अप्रैल-मई 2007 के दौरान केंद्र सरकार के वित्त में सुधार अधिक कर-राजस्व, अधिक गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों और न्यून योजना व्यय के कारण हुआ । सभी प्रमुख कर-राजस्व एक वर्ष पहले की तुलना में अधिक थे; निगम कर से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में तिगुना से भी अधिक बढ़ गया । अप्रैल-मई 2007 के दौरान सकल व्यय अप्रैल-मई 2006 से कम हुआ, जिसका कारण था योजना राजस्व व्यय में कमी होना (सारणी 17)।

केंद्रीय बजट का वित्तपोषण

वर्ष 2007-08 के दौरान राजकोषीय घाटा अधिकतर बाजार से उधार लेकर वित्तपोषित किया जाता रहेगा । बजट अनुमानों के अनुसार निवल बाजार उधार वर्ष 2007-08 में जीएफडी के 73.4 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगे, जबकि वर्ष 2006-07 में संशोधित अनुमान में यह प्रतिशत 72.5 था । निवल बाजार उधारों में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत बजट में 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि सम्मिलित नहीं है । एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियाँ सरकार के नकदी शेष में बनी हुई हैं और वे जीएफडी के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध नहीं हैं ।

दिनांकित प्रतिभूतियों और 364-दिवसीय खजाना बिलों (एमएसएस के अंतर्गत आबंटन को छोड़कर) के माध्यम से निवल बाजार उधार वर्ष 2007-08 के लिए 1,09,579 करोड़ रुपये पर रखे गये हैं । 79,249 करोड़ रुपये की अदायगी सहित सकल बाजार उधार की राशि 1,88,828 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । वर्ष 2007-08 की पहली छमाही के लिए निर्धारित 92,000

सारणी 17: केन्द्र साकार के वित्त : अप्रैल-मई 2007

(करोड़ रुपये)

मद	2007-08 (बजट अनुमान)	अप्रैल-मई		बजट अनुमानों का प्रतिशत अप्रैल-मई	
		2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व प्राप्ति (i + ii)	4,86,422	19,330	25,899	4.8	5.3
i) कर राजस्व	4,03,872	15,087	21,725	4.6	5.4
ii) करेतर राजस्व	82,550	4,243	4,174	5.6	5.1
2. ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	43,151*	500	2,716	4.2	6.3
3. योजनेतर व्यय	4,75,421*	62,882	67,615	16.1	14.2
जिसमें से :					
i) ब्याज अदायगी	1,58,995	23,919	26,221	17.1	16.5
ii) रक्षा	96,000	6,314	6,770	7.1	7.0
iii) सब्सिडी	51,247	11,412	15,508	25.5	30.3
4. योजना व्यय	2,05,100	29,036	23,135	16.8	11.3
5. राजस्व व्यय	5,57,900	87,950	85,234	18.0	15.3
6. पूँजीगत व्यय	1,22,621*	3,968	5,516	5.2	4.5
7. कुल व्यय	6,80,521*	91,918	90,750	16.3	13.3
8. राजस्व घाटा	71,478	68,620	59,335	81.0	83.0
9. सकल राजकोषीय घाटा	1,50,948	72,088	62,135	48.5	41.2
10. सकल प्राथमिक घाटा	-8,047	48,169	35,914	543.5	-446.3

* : भा. स्टेट बैंक में भा.रि.बैंक के हिस्से को सरकार को अंतरित करने से संबंधित लेनदेन संबंधी 40,000 करोड़ रु. की राशि शामिल है ।

स्रोत : लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।

करोड़ रुपये (वर्ष 2006-07 की तदनुकूल अवधि में 89,000 करोड़ रुपये) की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम का कैलेंडर केंद्र सरकार के परामर्श से मार्च 30, 2007 को जारी किया गया । वर्ष 2007-08 के दौरान (जुलाई 26, 2007 तक) 73,000 करोड़ रुपये की राशि की दिनांकित प्रतिभूतियों का वास्तविक निर्गम हुआ, जबकि कैलेंडर में 68,000 करोड़ रुपये की राशि के लिए निर्गम निर्धारित किया गया था । सभी नीलामियाँ संकेतित निर्गम कैलेंडर के अनुसार की गयीं, सिवाय एक नीलामी के, जो 5,000 करोड़ रुपये के लिए जून 12, 2007 को की गयी थी । सभी नीलामियाँ वर्तमान प्रतिभूतियों के पुनः निर्गम के रूप में की गयी थीं, सिवाय एक नये निर्गम (10-वर्षीय प्रतिभूति) के, जो 6,000 करोड़ रुपये के लिए जुलाई 6, 2007 को की गयी (सारणी 18) । प्राथमिक व्यापारियों को कोई अंतरण नहीं किया गया । सकल और निवल बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियाँ और 364-दिवसीय खजाना बिल) वर्ष 2007-08 के दौरान (जुलाई 26, 2007 तक) की राशि क्रमशः 85,628 करोड़ रुपये और 46,047 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष के लिए 45.3 प्रतिशत और 42.0 प्रतिशत अनुमानित उधार के लिए जवाबदेह थे । पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि के दौरान सकल और निवल उधार वर्ष 2006-07 के लिए वास्तविक उधार के लिए

सारणी 18: 2007-08 के दौरान जारी केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ

(राशि करोड़ रु. में/परिपक्वता वर्षोंमें आय प्रतिशत में)

क्रम सं.	निर्गम नीलामी कैलेंडर के अनुसार उधार			वास्तविक उधार			
	नीलामी की अवधि	राशि	अवशिष्ट परिपक्वता	नीलामी की तारीख	राशि	अविशिष्ट परिपक्वता	आय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5-12 अप्रैल 2007	6,000	5-9	12 अप्रैल 2007	6,000	8.39	8.16
		4,000	20 और अधिक	12 अप्रैल 2007	4,000	29.15	8.58
2.	20-27 अप्रैल 2007	6,000	10-14	27 अप्रैल 2007	6,000	9.71	8.16
3.	4-11 मई 2007	6,000	10-14	11 मई 2007	6,000	9.92	8.31
		4,000	20 और अधिक	11 मई 2007	4,000	29.06	8.64
4.	18-25 मई 2007	5,000	5-9	25 मई 2007	5,000	8.26	8.24
		3,000	15-19	25 मई 2007	3,000	14.96	8.40
6.	1-8 जून 2007	6,000	10-14	5 जून 2007	6,000	9.86	8.18
		3,000	20 और अधिक	5 जून 2007	3,000	29.00	8.52
				12 जून 2007 *	5,000	9.84	8.44
7.	15-22 जून 2007	6,000	10-14	15 जून 2007	6,000	9.83	8.35
8.	6-13 जुलाई 2007	6,000	10-14	6 जुलाई 2007	6,000	10.00	7.99
		4,000	20 और अधिक		4,000	28.93	8.45
9.	20-27 जुलाई 2007	6,000	5-9	20जुलाई 2007	6,000	6.11	7.56
		3,000	20 और अधिक		3,000	25.10	8.34

ज्ञापन :

वर्ष	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत आय
2003-04	14.94	5.71
2004-05	14.13	6.11
2005-06	16.90	7.34
2006-07	14.72	7.89
2006-07 (26 जुलाई 2006 तक)	14.88	7.86
2007-08 (26 जुलाई 2007 तक)	14.10	8.25

* : गैर - अनुसूचित

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

क्रमशः39.5 प्रतिशत और 31.3 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार थे । वर्ष 2007-08 के दौरान (जुलाई 26, 2007 तक) जारी की गयी दिनांकित प्रतिभूतियों की 14.10 वर्ष पर भारित औसत परिपक्वता अवधि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि के दौरान 14.88 वर्ष पर भारित औसत परिपक्वता अवधि से कम थी। इसी अवधि में जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत आय 7.86 प्रतिशत से बढ़कर 8.25 प्रतिशत हो गयी ।

केंद्रीय सरकार के परामर्श से वर्ष 2007-08 के लिए अर्थोपाय अग्रिमों (डब्लूएमए) की सीमा छमाही आधार पर निर्धारित की गयी, जबकि एक वर्ष पहले यह तिमाही आधार पर थी । वर्ष 2007-08 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) के लिए डब्लूएमए की सीमा 20,000 करोड़ रुपये रखी गयी, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में यह पहली तिमाही के लिए 20,000 करोड़ रुपये और दूसरी छमाही के लिए 10,000 करोड़ रुपये थी; दूसरी छमाही (अक्तूबर से मार्च) के लिए यह 6,000 करोड़ रुपये होगी, जो उतनी ही है, जैसाकि एक वर्ष पूर्व तीसरी और चौथी तिमाहियों के लिए थी । रिज़र्व बैंक ऐसा लचीलापन रखता है कि यह किसी भी समय संक्रमणकालीन मुद्दों और अभिभावी परिस्थितियों पर विचार करते हुए भारत सरकार के परामर्श से इन सीमाओं में संशोधन कर सके । डब्लूएमए और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर, जैसाकि यह पूर्ववर्ती वर्ष में थी, क्रमशः रेपो दर और रेपो दर से ऊपर दो प्रतिशत अंक होगी ।

केंद्र सरकार के पास मार्च 2007 के अंत में 50,092 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि दर्ज की गयी। सामान्य मौसमी पैटर्न को प्रतिबिंबित करते हुए नकदी शेष अप्रैल 2007 के दौरान तेजी से कम हो गये, जिसके कारण अप्रैल 27, 2007 को डब्लूएमए का आश्रय लेना आवश्यक हो गया । जून के अंत में सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक की भारतीय स्टेट बैंक में अंशधारिता का अभिग्रहण करने के कारण केंद्र सरकार की नकदी स्थिति पुनः दबाव में आ गयी। वर्ष 2007-08 के दौरान (जुलाई 20, 2007 तक) केंद्र ने 72 दिनों के लिए डब्लूएमए का आश्रय लिया, जबकि वर्ष 2006-07 की इसी अवधि में 33 दिनों के लिए डब्लूएमए का आश्रय लिया गया था । वर्ष 2007-08 के दौरान (जुलाई 20, 2007 तक) केंद्र ने तीन अवसरों पर ओवरड्राफ्ट लिया; जबकि पिछले वर्ष केंद्र ने कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया था ।

राज्यों के वित्त : वर्ष 2007-08[1]

राज्य सरकारों ने वर्ष 2007-08 के लिए अपने बजटों में राजस्व बढ़ाने और व्यय प्रबंध में सुधार लाने के उद्देश्य से किये जाने वाले उपायों के माध्यम से राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनेक नीतिगत पहल करने का प्रस्ताव किया । कुछ राज्य सरकारों ने राज्य पीएसयू के कार्य करने की व्यापक समीक्षा और उनकी पुनर्संरचना का प्रस्ताव किया। विद्युत बोर्डों की वित्तीय व्यवहार्यता पुनः बहाल करने के लिए कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये । उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने बिक्री कर के बदले में अप्रैल 1, 2007 से मूल्य वर्धित कर प्रणाली (वैट) को क्रियान्वित किया । 11वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के विकास को दी गयी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने विविध परियोजनाओं, खासकर बिजली और सड़कों की, के कार्यान्वयन की परिकल्पना की है, जो सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से की जायेगी । राजकोषीय दायित्व विधान (एफआरएल) को 25 राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किया गया है (मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार) ।

[1] 27 राज्य बजटों (एनसीटी दिल्ली सहित), जिनमें से दो लेखानुदान हैं, संबंधी सूचना पर आधारित ।

राजकोषीय समेकन के लिए किये जाने वाले प्रयासों को प्रतिबिंबित करते हुए राज्य सरकारों ने वर्ष 2007-08 में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत राजस्व अधिशेष का बजट बनाया है, जबकि पिछले वर्ष राजस्व लेखा में लगभग संतुलन की स्थिति थी । परिणामस्वरूप, जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा बजट में वर्ष 2007-08 में कम होकर 2.1 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि एक वर्ष पहले यह 2.6 प्रतिशत था (देखें सारणी 15) । वर्ष 2007-08 में राजकोषीय सुधार मुख्यतः राजस्व व्यय में वृद्धि को काबू में रख कर लाने का प्रस्ताव है; इसके परिणामस्वरूप बजट में राजस्व व्यय-जीडीपी अनुपात वर्ष 2006-07 के 12.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2007-08 में 12.2 प्रतिशत रहने की संभावना है । जीडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ बजट में वर्ष 2007-08 में 12.5 प्रतिशत पर बनाये रखी जायेंगी; राजस्व के प्रमुख अवयव, यथा, राज्य का अपना राजस्व (कर और करेतर) और चालू न्यागमन और अंतरण वर्ष 2007-08 में जीडीपी के क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 5.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगे ।

राज्यों के बजटों का वित्तपोषण

वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यों के लिए (चार राज्य सरकारों को छोड़कर, जिनके लिए वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है) बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत अनंतिम निवल आबंटन 21,434 करोड़ रुपये रखा गया है । 11,554 करोड़ रुपये की अदायगी और 335 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन को हिसाब में लेते हुए वर्ष 2007-08 के लिए सकल आबंटन राशि 33,323 करोड़ रुपये होती है, जबकि वर्ष 2006-07 के लिए वास्तविक उधार की राशि 20,825 करोड़ रुपये थी । वर्ष 2007-08 के दौरान (जुलाई 26, 2007 तक) चौदह राज्यों ने 8.00-8.57 प्रतिशत की सीमा में अधिकतम आय के लिए नीलामी द्वारा बाजार ऋण से 8,542 करोड़ रुपये की राशि जुटाई (सकल आबंटन का 25.6 प्रतिशत), जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि में 7.65-8.66 प्रतिशत की सीमा में कट ऑफ आय पर 7,343 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गयी थी । वर्ष 2007-08 के दौरान अबतक सभी निर्गम 10-वर्षीय परिपक्वता अवधि के लिए किये गये हैं, जैसाकि

सारणी 19 : 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार

मद	दिनांक	कट ऑफ दर (प्रतिशत)	अवधि (वर्ष)	जुटाई गई राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
नीलामियां				
i. पहली	19 अप्रैल 2007	8.30	10	1,837
ii. दूसरी	10 मई 2007	8.34	10	350
iii. तीसरी	17 मई 2007	8.40	10	1,400
iv. चौथी	19 जून 2007	8.45-8.57	10	3,566
v. पांचवी	26 जुलाई 2007	8.00-8.25	10	1,389
कुल जोड़				**8,542**
ज्ञापन				
वर्ष				**भारित औसत आय (प्रतिशत)**
2003-04				6.13
2004-05				6.45
2005-06				7.63
2006-07				8.10
2006-07 (26 जुलाई 2006 तक)				8.08
2007-08 (26 जुलाई 2007 तक)				8.35

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

चार्ट 6: राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग

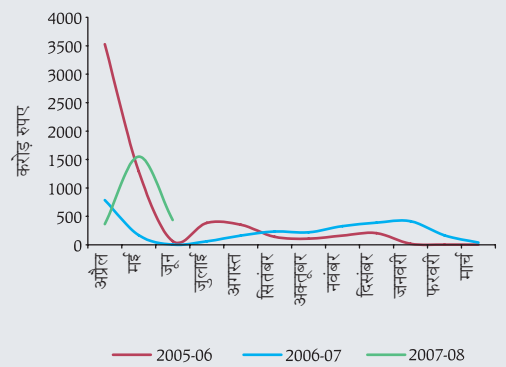

* : दैनिक बकाया कर औसत

चार्ट 7: राज्य सरकारों द्वारा खज़ाना बिलों में निवेश

* : शुक्रवार को बकाया कर औसत

पिछले वर्ष किया गया था। बाजार ऋणों की भारित औसत ब्याज दर वर्ष 2007-08 के दौरान (जुलाई 26, 2007 तक) बढ़कर एक वर्ष पहले के 8.08 प्रतिशत की तुलना में 8.35 प्रतिशत हो गयी (सारणी 19)। केंद्र सरकार प्रतिभूतियों की तदनुकूल आय पर स्प्रेड 11 से लेकर 36 आधार अंक तक था।

वर्ष 2007-08 के दौरान (जुलाई 20, 2007 तक) राज्यों द्वारा डब्लूएमए और ओवरड्राफ्ट का औसत दैनिक उपयोग 694 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि में यह 258 करोड़ रुपये था (चार्ट 6)। वर्ष 2007-08 के दौरान (जुलाई 20, 2007 तक) तीन राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का आश्रय लिया, जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि के दौरान दो राज्यों ने ओवरड्राफ्ट लिया था।

राज्यों की नकदी अधिशेष स्थिति, जो खजाना बिलों (14-दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल और नीलामी खजाना बिल) में उनके निवेश में प्रतिबिंबित होती है, जुलाई 20, 2007 को 75,321 करोड़ रुपये थी, जबकि जून 2007 के अंत में 76,930 करोड़ रुपये और मार्च 2007 के अंत में 80,768 करोड़ रुपये थी। अप्रैल-जून 2007 के दौरान खजाना बिलों में राज्यों का औसत निवेश 68,800 करोड़ रुपये का हुआ, जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि में यह 52,876 करोड़ रुपये का हुआ था (चार्ट 7)।